ISSN 2348-3857

# बदलती परिस्थितियों में भारत-नेपाल सम्बन्ध एवं चीन

Research Reinforcement
ISSN 2348-3857

**डॉ. अनुराधा सिंह**

सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान
शा.श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय, सीतापुर, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़)

**शोध सारांश**

*भारत व नेपाल भूगोल, इतिहास, संस्कृति, भाषा, धर्म, विवाह यहाँ तक कि पौराणिक कथाओं को साझा करते हैं। लेकिन इसी के साथ ही दोनों के बीच गलतफहमियाँ और अविश्वास भी कम नहीं है। इन दोनों के बीच स्थित अविश्वास और गलतफहमियों का फायदा कहीं न कहीं चीन को मिला है। भारत-नेपाल संबंधों में चीन एक महत्वपूर्ण तत्व है। नेपाल में चीन ने आर्थिक सहायता व अवसंरचनात्मक विकास के माध्यम से भारत के बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश की है। जबकि नई दिल्ली उसी पुराने राग को अलाप रही है कि - '' दक्षिण एशिया भारत के प्रभाव का विशिष्ट क्षेत्र है। '' भारत का यही रवैया नेपाल के मन में भय उत्पन्न करता है और वह अपनी सम्प्रभुता, स्वतंत्रता व समानता का प्रदर्शन करने के लिए भारत का विरोध करता है और उसे संतुलित करने के लिए चीन की ओर देखता है। तिब्बत के अधिग्रहण के पश्चात् भारत की सुरक्षा बहुत कुछ नेपाल पर निर्भर करती है। अतएव बदलती परिस्थितियों में दोनों के संबंधों को नए सिरे से देखने की आवश्यकता है।*

दक्षिण एशिया में भारत आकार, जनसंख्या, शक्ति सामर्थ्य, संभावना और क्षमता की दृष्टि से अपने पड़ोसी देशों की तुलना में काफी बड़ा है। उत्तर में स्थित नेपाल के साथ भारत के गहन ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक एवं भौगोलिक समानताएँ विद्यमान हैं। नेपाल की भौगोलिक स्थिति जहाँ एक ओर इसे भारत के लिए महत्वपूर्ण स्थिति वाला देश बना देता है, वहीं दूसरी और नेपाल का भू-आबद्ध राष्ट्र होना इसे काफी हद तक भारत पर निर्भर बना देता है।[1] तिब्बत पर चीन के आधिपत्य के पश्चात् यह भारत व चीन के मध्य एक अवरोधक राज्य का काम करता है। चीन द्वारा तिब्बत को हस्तगत करने के पश्चात् से नेपाल का सामरिक महत्व भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बढ़ गया है। नेपाल के लिए यह एक विशिष्ट समस्या है कि इसे अपने सभी विदेशी आपूर्ति के लिए भारत पर निर्भर रहना पड़ता है और यह केवल भारत के माध्यम से पारगमन प्राप्त कर सकता है और भारत पर ज्यादा निर्भरता इसके लिए शोषणकारी हो सकता है। अतएव वह साम्यता स्थापित करने के लिए चीन की उपस्थिति भी चाहता है। नेपाल राजतंत्र के बाद से भारत के साथ चीन कार्ड खेल रहा है और सबसे हाल में एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत के रूप में माओवादियों के उद्भव ने भारत को चिंतित किया है क्योंकि इसका प्राकृतिक झुकाव चीन की ओर है। भारत के नेपाल में कुछ राजनीतिक हित हैं तो नेपाल के भारत के साथ आर्थिक हित हैं। यह अनुभव किया गया है कि भारत जब भी नेपाल में कुछ राजनीतिक पक्ष चाहता है तो वह आर्थिक कार्ड का खेल खेलना शुरू कर देता है।

1949 में चीन में कम्युनिष्ट शासन की स्थापना और तिब्बत में उसकी बढ़ती गतिविधियों के कारण भारत चिंतित था क्योंकि नेपाल पर यदि कोई संकट आता तो उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ता। अतएव भारत व नेपाल के मध्य 31 जुलाई 1950 को दो संधियाँ - शांति और मैत्री की संधि और व्यापार और वाणिज्य की संधि सम्पन्न की गई। काठमांडू में हुई इस संधि के फलस्वरूप भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से नेपाल की सुरक्षा का दायित्व अपने उपर ले लिया और अन्य किसी राष्ट्र से सुरक्षा संबंध स्थापित करने से पूर्व भारत की सहमति को आवश्यक माना गया।

1956 के बाद से नेपाल का झुकाव चीन की ओर होने लगा क्योंकि कहीं न कहीं 1956 के पूर्व की भारत की नीतियाँ नेपाल पर ज्यादा प्रभुत्व जमाने वाली थीं। इसके साथ-साथ 1954 की भारत-चीन व्यापार संधि, जिसके अंतर्गत तिब्बत पर चीन का आधिपत्य स्वीकार कर लिया गया था, ने नेपाल

ISSN 2348-3857

को असमंजस की स्थिति में डाल दिया। दूसरी ओर 1955 में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्राप्ति के बाद नेपाल की स्थिति में थोड़ा परिवर्तन आया। इस कारण अब नेपाल का चीन की तरफ झुकाव स्पष्ट दिखाई देने लगा।

नेपाल के चीन के प्रति घनिष्ठ संबंधों का परिचय निम्नलिखित घटनाओं से स्पष्ट हो जाता है -

1. 1956 में नेपाल के प्रधानमंत्री की चीन यात्रा।

2. 20 सितम्बर 1956 को चीन व नेपाल के बीच मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए गए।

3. 1957 में चीन के प्रधानमंत्री चाऊ-एन-लाई नेपाल आए।

4. 5 अक्टूबर 1961 को चीन व नेपाल के बीच में सीमा संबंधी समझौता हुआ। नेपाल ने इस संदर्भ में भारत से कोई सलाह नहीं की, जबकि इसी प्रकार की संधि के संदर्भ में बर्मा ने भारत से सलाह की थी।

5. 16 अक्टूबर 1961 को नेपाल-चीन समझौते के आधार पर चीन ने नेपाल को ल्हासा से काठमांडू तक की सड़क निर्माण करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की। इस प्रकार के समझौतों से भारत को अपनी सुरक्षा हेतु चीन-नेपाल के इस बढ़ते संबंधों से आशंका होना स्वाभाविक था।

चीन 1955 से नेपाल में सक्रिय होने लगा था, 1956 में नेपाली प्रधानमंत्री ने चीन की यात्रा की। 20 सितम्बर 1956 को नेपाल व चीन के मध्य मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए। नेपाल में चीन की बढ़ती भूमिका तथा नेपाल का चीन की तरफ झुकाव भारत के लिए चिंताजनक बनता जा रहा था। भारत व नेपाल संबंध में चीनी पक्ष को अनदेखा नहीं किया जा सकता। नेपाल का उच्च राजनीतिक वर्ग भारत के साथ सस्ती सौदेबाजी के लिए चीनी चाल का इस्तेमाल करता आ रहा है और नया नेपाल चीन के साथ अधिक मित्रवत् हो गया है।[3] नेपाल अपने दोनों पड़ोसियों में से भारत को खतरे का बहुत बड़ा स्त्रोत मानता रहा है। तिब्बत पर चीनी अधिपत्य के पश्चात् नेपाल बदलते राजनीतिक परिदृश्य में भारत से घनिष्ठता नहीं चाहता था अपितु वह दोनों के बीच और पास तटस्थ रहना चाहता था। नेपाल सरकार भारत से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की अपेक्षा दोनों पड़ोसी राज्य भारत व चीन के मध्य एक अवरोधक राज्य के रूप में कार्य करना चाहती थी। इसी समय नेपाल राजशाही ने भारत के साथ अपने विशिष्ट संबंधों को ताक पर रखकर भारत के राष्ट्रहितों की परवाह न करते हुए चीन के साथ 26 अप्रैल 1960 को मैत्री व रक्षा संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए। इतना ही नहीं भारत की सुरक्षा की घोर उपेक्षा करते हुए उसने ल्हासा को काठमांडू को जोड़ने वाली सड़क निर्माण की अनुमति भी चीन को दे दी। 1962 में भारत व चीन के युद्ध के दौरान नेपाल का दृष्टिकोण तटस्थता का रहा, जिससे भारतीय भावनाओं को आघात पहुँचा।

नेपाल में चीनी तत्व की उपस्थिति भारत व नेपाल के मध्य तनाव उत्पन्न करने वाली रही है। वहाँ चीन की गतिविधियाँ भारत विरोधी एवं विध्वंसात्मक रही हैं, जून 1969 में शायद चीन के कहने पर नेपाल ने नेपाल-चीन सीमा की चौकियों पर स्थित भारतीय सेना के समन्वय समूह व तकनीकी अधिकारियों को वापस बुलाने को कहा।[4] इसके अतिरिक्त नेपाल के पूर्व नरेश महेन्द्र और नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री टांका प्रसाद आचार्य का रूझान भी चीन की ओर रहा है। चीन ने नेपाल को आकर्षित करने के लिए नेपालियों तथा चीनियों में एक ही रक्त-प्रवाह की बात को दोहराया।[5]

भारत नेपाल संबंधों में अनेक उतार-चढ़ाव आते रहे हैं तथा नेपाल का भी कहना है कि नेपाल एक सम्प्रभु राज्य है और वह भारत के साथ विशेष संबंध बनाए रखने हेतु बाध्य रही है। 1980 के दशक के अंतिम वर्षो में चीन की वजह से भारत व नेपाल के मध्य मतभेद बढ़ गया। 1988 में महाराजा वीरेन्द्र ने भारी मात्रा में चीन से हथियार खरीदे जो जून 1988 में काठमांडू-कोदारी मार्ग से होते हुए नेपाल पहुँचे। इन हथियारों की मात्रा 300 से 500 ट्रकों के बीच अनुमानित थी जिनमें एन्टी-एयरक्राफ्ट गन, मध्यस्तरीय प्रक्षेपास्त्र ए.के. 49 रायफल आदि सम्मिलित थे। भारत ने नेपाल की इस खरीददारी को 1950 की संधि के विरुद्ध बताया तथा इन हथियारों के भारत के विरुद्ध प्रयोग होने की नीयत से नेपाल की भर्त्सना की।

भारत-नेपाल संबंध में 1990 के पश्चात् दृढ़ता आई। नेपाल में 1990 के बाद लोकतांत्रिक आंदोलन की विजय के पश्चात् प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने भी भारत से मधुर संबंध बनाने का प्रयास किया। उन्होनें अपने संवाद में चीन से हथियारों का आयात बन्द करने पर सहमति जताई। 1996 में नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने भारत यात्रा के दौरान आश्वासन दिया कि किसी अन्य देश से हथियार खरीदने से पहले नेपाल भारत के साथ विचार विमर्श करेगा।

1990 से 2000 तक का दौर आंतरिक राजनीति में उथल-पुथल व माओवादी हिंसा से भरा रहा। इसी उथल-पुथल

के दौर में 26 अप्रैल 2006 को संसद बहाली की घोषणा हुई। भविष्य में नेपाल की राजनीतिक स्थिरता सबसे बड़ी चुनौती होगी। नई सरकार अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध रखना चाहेगी क्योंकि माओवादी तथा साम्यवादी दल अवश्य चाहेंगे कि चीन को नेपाल के साथ रिश्तों में पर्याप्त स्थान मिले।

## नेपाल में चीन का बढ़ता प्रभाव

### साँस्कृतिक प्रभाव

चीन की नेपाल में दिलचस्पी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। विश्लेषक मानते हैं कि चीन की नेपाल में बढ़ती दिलचस्पी थोड़े वक्त के लिए नहीं है बल्कि वो अगले 25-30 साल की योजना के तहत् यह काम कर रहा है। चीन ने नेपाल के साथ साँस्कृतिक आदान-प्रदान शुरू किया है। चीन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह 100 नेपाली विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान करता है। काठमांडू विश्वविद्यालय के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट और अंतर्राष्ट्रीय भाषा संस्थान में चीनी भाषा और संस्कृति सिखाने के लिए बाकायदा अध्यापकों को चीन से काठमांडू भेजा गया है। दशकों तक भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आभा मण्डल में रहने के बाद अब नेपाल बाँहे फैलाकर हिमालय पार के अपने पड़ोसी देश चीन का स्वागत करने को तैयार है। और आने वाले वर्षो में नेपाल में अपनी भूमिका बढ़ने की संभावना को पहचानते हुए चीन ने भी हर क्षेत्र में सक्रियता बढ़ा दी है। नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक युवराज धिमिर का कहना है कि चीन खुद को दुनिया के साथ बड़े शिक्षा केन्द्रों में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब नेपाल के भावी नेता पहले की तरह इलाहाबाद और वाराणसी में शिक्षित होने के बजाय बीजिंग और शंघाई से पढ़कर आए।

नेपाल की राजनीति में भारत का गहरा प्रभाव रहा है लेकिन वहाँ भारतीय मंसूबों को लेकर आम लोगों में गहरी आंशका भी है। तथ्य यह भी है कि नेपाल के नौजवान अपने देश में चीन की बढ़ती दिलचस्पी को एक अवसर के तौर पर देखते हैं। नेपाली युवक चीनी भाषा सीखने में अधिक दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उनका मानना है कि चीन की जनसंख्या डेढ़ अरब है और अगर इसका एक प्रतिशत टूरिस्ट भी नेपाल आते हैं तो हमें रोजगार की कोई कमी नहीं रहेगी।[6]

### आर्थिक प्रभाव

आर्थिक क्षेत्र में भी चीन अपनी गहरी पैठ बनाता जा रहा है। नेपाल में एफडीआई के मामले में चीन, भारत व अमेरिका के बाद तीसरा महत्वूपर्ण देश बन गया है। पिछले कुछ वर्षों में चीन और नेपाल के मध्य में व्यापार तेजी से बढ़ा है। नेपाल के साथ विदेश व्यापार में चीन का अंश जहाँ 2009 में 11 प्रतिशत था वही 2011 में यह बढ़कर 19.4 हो गया। 2013-14 में चीन ने नेपाल के 119 परियोजनाओं में निवेश किया तो भारत ने केवल 22 परियोजनाओं में। नेपाल को दी जाने वाली चीनी सहायता राशि भी साल दर साल बढ़ती जा रही है। जिसका उद्देश्य नेपाल में भारत व अमेरिका के प्रभाव को रोकना है। 2011 में उसने नेपाल को 32.5 मिलियन डालर की सहायता दी। चीन द्वारा नेपाल को प्रदान की जाने वाली सहायता का मकसद सामरिक व राजनीतिक है। चीन इस क्षेत्र में नेपाल को स्वतंत्र व तटस्थ रखना चाहता है ताकि उसके हितों पर आँच न आए।

चीन के सहयोग से काठमांडू में आठ लेन का रिंग रोड बनाया जा रहा है। चीन की शंघाई कंस्ट्रक्शन ग्रुप कम्पनी लिमिटेड अभी पहले चरण का काम कर रही है। तीन चरणों में बन रहा 27 किलोमीटर लम्बा यह रिंग रोड मई 2016 में पूरा होने की उम्मीद है। चीन की बनाई यह सड़क काठमांडू से तिब्बत को जोड़ती है। जिस इमारत में नेपाल के संविधान पर बहस चल रही है, उसे करीब 15 पहले चीन ने ही बनाया था। इतना ही नहीं दक्षेस शिखर सम्मेलन जिस भवन में आयोजित किया गया उसे भी चीन ने निर्मित किया है।

चीन ने अपने हितों की पूर्ति के लिए नेपाल के उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ उसके ढांचागत विकास पर बल दिया जिससे नेपालियों की भारत पर से आर्थिक निर्भरता कम हो। वहीं भारत ने सदैव नेपाल का हित चाहा है। भारत द्वारा निर्मित सड़क के माध्यम से नेपाल के लिए न केवल भारतीय बाजार सुगम हो गया अपितु इसने सस्ते श्रमिकों के रोजगार के लिए भारत के द्वार खोल दिए।

नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता, आंतरिक संघर्ष व चीन की उपस्थिति ने भारत नेपाल संबंधों को प्रभावित किया है। नेपाल की साम्यवादी पार्टी के नेताओं का झुकाव चीन की तरफ होने के कारण यदाकदा वे खुलेआम भारत पर आरोप लगाते रहे हैं कि भारत नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। जिससे उसकी सम्प्रभुता प्रभावित होती है। नेपाल की ओर से हमेशा यह वृहद मांग रखी जाती रही कि जुलाई 1950 की मैत्री और शांति की भारत-नेपाल संधि और पारगमन, वाणिज्य और व्यापार पर संधि, जिस पर उसी साल हस्ताक्षर हुए, में निहित कुछ दिशा निर्देशक सिद्धांतों का पुनरावलोकन किया जाए। नेपाल शायद 1950 की संधि के अनुच्छेद 2 व 5 में परिवर्तन या संशोधन का

इच्छुक हो। 1950 की संधि के अनुच्छेद 2 के प्रावधान इस प्रकार हैं, ''दोनों सरकारें एतद् द्वारा यह जिम्मा लेती हैं कि किसी भी पड़ोसी देश के साथ गंभीर विवाद या गलतफहमी की स्थिति होने पर, जिससे दोनों सरकारों भारत व नेपाल के बीच बने हुए मैत्रीपूर्ण रिश्तों में दरार पड़ने की आशंका हो, वे एक दूसरे को इस संबंध में सूचित करेंगी। अनुच्छेद 5 के अनुसार, नेपाल की सरकार नेपाल की सुरक्षा के लिए जरूरी उपकरणों और युद्ध के साजो सामान या शस्त्र और गोला बारूद भारतीय क्षेत्रों से और इनसे होकर आयात करने के लिए स्वतंत्र होंगी। इस व्यवस्था पर अमल की प्रक्रिया को दोनों सरकारें मिलकर तय करेंगी। नेपाल यह महसूस करता है कि ये अनुच्छेद इसके विदेश संबंधों के निर्वाह और इसकी रक्षा और सुरक्षा नीतियों की रूपरेखा तैयार करने में इसके संप्रभु विवेकाधिकार पर रोक लगा रहे हैं। जबकि वास्तविकता इससे परे है।[7] ऐसी स्थिति में भारत का नजरिया नेपाल द्वारा अपने विकल्पों का इस्तेमाल करने के हक को मान्यता देना होना चाहिए। पर इसी के साथ-साथ नेपाल को एक स्पष्ट और सुनिश्चित संदेश देना भी है कि नेपाल के अंदर चीन की किसी भी अतिरिक्त लिप्तता की योजनाओं से निपटने के लिए भारत को आवश्यक उपाय करने होंगे और अपनी सुरक्षा के लिए भारत रणनीतिक, विदेश नीति और रक्षा योजनाओं के रास्ते जो कुछ भी आवश्यक होगा, करेगा।[8]

यह अतिश्योक्ति न होगी कि चीन को अपने एकमात्र उद्देश्य को प्राप्त करने में सफलता मिली और वह उद्देश्य है- अपने सीमाओं की सुरक्षा करना तथा अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना। अपने इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के अनुपात में उसने नेपाल को सहायता दी। इसके विपरीत नेपाल में भारत के उद्देश्य भिन्न-भिन्न थे, दिशाएँ दिग्भ्रमित थी और प्राय: मत विरोधाभासी थे, जिससे उसकी सहायता की प्रकृति उलझ कर रह गई।

भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जब अगस्त 2014 में नेपाल गये तो पिछले 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली नेपाल यात्रा थी। पिछले सत्रह वर्षों में पश्चिमी देशों और चीन ने नेपाल में सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव बढ़ाया है। दूसरी तरफ इन 17 वर्षों में नेपाल में भारत का प्रभाव कम हुआ, भारत के प्रति कटुता बढ़ी और चीन ने भारी निवेश करके अपनी पकड़ मजबूत की। विश्लेषकों का तो यह मानना है कि भारत सरकार ने नेपाल में अपनी नीतियों को नौकरशाहों के हाथ में छोड़ दिया था, जिससे नेपाल की जनता में भारत के प्रति संशय बढ़ा। इसका फायदा चीन जैसे देशों ने उठाया है। काठमांडू में चीनी पर्यटक नेपाल की यात्रा कर रहे हैं जिसका प्रतिकूल असर नेपाल की, प्रधानमंत्री द्वारा 17 वर्ष पश्चात् की गई यात्रा बेहद प्रासंगिक है जो भविष्य में भारत नेपाल संबंधों पर प्रभाव डालेगी। प्रधानमंत्री फोर-सी एजेन्डे के साथ नेपाल गए थे। फोर-सी अर्थात् कॉपरेशन (सहयोग), कल्चर (संस्कृति), कनेक्टविटी (संयोजकता) और कॉन्स्टीट्यूशन (संविधान)। जिसमें उन्हें काफी हद तक सफलता मिली। आशा है कि रिश्तों में आई यह सकारात्मकता दोनों देशों के बीच के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को एक ऊँचाई देगी। हमारा ध्येय यह होना चाहिए कि हम नेपाल को यह आश्वासन दें कि भारत उसके साथ समानता और परस्पर आदर के आधार पर और परस्पर लाभ के लिए स्थायी भागीदारी का इच्छुक है। हमें नेपाल को अपने पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक और व्यापार सामर्थ्य को हासिल करने में अवश्य मदद करनी चाहिए।

सकारात्मक महौल के बावजूद यह कहना जल्दबाजी होगा कि भारत और नेपाल में सभी मतभेद दूर हो गए हैं। नेपाल में युद्ध से शांति, राजतंत्र से गणतंत्र, हिन्दू राष्ट्र से धर्म निरपेक्ष राज्य, एकात्मक से संघात्मक का सफर जारी है। संविधान का प्रारूप तैयार हो रहा है भारत को ऐसी नीतियॉ बनानी होंगी जो न केवल नेपाल और भारत के लिए हितकर हो अपितु चीन के बढ़ते प्रभाव को भी रोक सके।

**संदर्भ सूची**


1. यादव, आर.एस., भारत की विदेश नीति, प्रकाशक-डार्लिंग किंडरस्ले (इंडिया) प्रा. लिमिटेड (पियर्सन) 2013 पृ. 208
2. वही, पृ. 209
3. वर्ल्ड फोकस, अक्टूबर 2014 पृ. 98
4. यादव, आर.एस., वही, पृ. 211
5. वर्ल्ड फोकस वही पृ. 98
6. http:// www.bbc.co.uk/india/2013/04/130426-china-nepal-india
7. दीक्षित, जे.एन., भारत की विदेश नीति और उसके पड़ोसी, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2005 पृ. 256-257
8. वही, पृ. 258